REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 5 | FEBRUARY - 2019

गाँधी जी के द्वारा असहयोग आन्दोलन के स्थगन की प्रतिक्रियात्मक भूमिका।

अंजली शर्मा
शोधार्थी इतिहास विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,
कामेश्वर नगर, दरभंगा।

महात्मा गाँधी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह प्रथम जन्म आन्दोलन था। इसमें असहयोग की नीति प्रमुखतः से अपनायी गई। इस आन्दोलन का व्यापक जन्म आधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस प्रकार यह प्रथम जन आन्दोलन बन गया। आन्दोलन की प्रगति के साथ–साथ आन्दोलन को दबाने के लिए सरकार का दमन चक्र बहुत तेजी से चलने लगा। सभी प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओ को जेल की चारदिवारी के भीतर डाल दिया गया। सार्वजनिक संस्थाओ का गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। सन् 1921 के अंत तक राजनितिक कैदियो की संख्या पचास हजार हो गई। फरवरी 1922 को महात्मा गाँधी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर सरकार की कठोर नीति की निन्दा करते हुए उसे चेतावनी दी कि यदि सरकार अपनी नीति में परिवर्तन नही करती तो सात दिनो के अंदर वह बारदोली में सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारंभ कर देंगे। लेकिन अभी सात दिन की अवधी समाप्त नहीं हुई थी किस चौरि–चौरा में एक अप्रत्याशित हिंसक घटना घटी।

12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आन्दोलन को समाप्त करने के निर्णय के बारे में गाँधीजी ने 'यंग इंण्डिया' में लिखे एक लेख में गाँधी जी ने आन्दोलन वापस लिए जाने की नीति के समर्थन में कहा कि अहिंसा के लिए एक परमावश्यक विश्वास है। वह हर प्रकार का अपमान 'यातना' बहिष्कार और मृत्यु तक को स्वीकार करने को तैयार थे ताकि आन्दोलन हिंसात्मक न हो जाए।

सुभाषचन्द्र बोस ने गाँधी पर यह आरोप लगया कि उन्होने एक तानाशाह को रूप में कार्य किया। भिन्न–भिन्न प्रांतो के प्रतिनिधियो से परामर्श के बिना ही आन्दोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। जिस समय जनता मे उत्साह ओर जोश चरम सीमा पर पहुँचने ही वाला था, ठीक उसी वक्त पीछे हटने का आदेश देना संपूर्ण राष्ट्र के लिए महान दुर्घटना थी। 1 उनहोने गाँधी जी पर जनांदोलन का गला घोटने का दोष भी लगाया। बोस ने कहा की आन्दोलन में कुछ त्रुटिया आरंभ से ही अंतर्निहित थी और शनैः शनैः उन्होने ने अपने आप को प्रकट करना आरंभ कर दिया। सबसे प्रमुख त्रुटि यह थी कि एक ही व्यक्ति को अत्यधिक शक्ति और उत्तरदायित्व दे दिया था।

जवाहरलाल नेहरू ने भी आन्दोलन स्थगित किए जाने पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि, ''इतने बड़े आन्दोलन को अचानक रोक देने से देश में एक के बाद एक दुखद घटनाओ का क्रम शुरू हुआ। इससे राजनीतिक संघर्ष में छुटपुट और निरर्थक हिंसा की प्रवृत्ति तो रूक गई किन्तु

इस की हुई हिंसा को रास्ता तो ढूढ़ना ही था और बाद के संधर्षो में शायद इसने ही सांप्रदायिक दंगो को बढ़ावा दिया।''2

रजनी पाम दत्त ने भी आन्दोलन स्थगित होने पर अपना असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि ''गाँधीजी सहित कांग्रेस नेताओ ने आन्दोलन को वापस इसलिए ले लिया कि उन्हे यह भय था कि इससे जनता में आन्दोलन फैल जायेगा और वे जनता के आन्दोलन से डरते थे। क्योकि इससे संपत्ति वाले वर्ग के हितो को भय था और स्वयं इस संपत्ति वाले वर्ग के साथ मिले हुए थे।''3 डी. ए. लो. ने अपनी पुस्तक कांग्रेस एण्ड द राज मे यह राय व्यक्त की है कि यह सब विलियम विनसेंट के अनुरूप हुआ। विनसेट गाँधी के इस आन्दोलन को इतनी लम्बी रस्सी दे देना चाहते थे जिसमें उलझकर वह स्वयं मर जाए। डी. ए. लो, के अनुसार विनसेट की यह नीति बहुत सफल रही थी क्योकि इससे असहयोग आन्दोलन समाप्त हो गया।

मोतीलाल नेहरू तथा लाजपत राय ने जेल से कार्यकारिणी के फैसले के विरूद्व गाँधी को खत लिखा। एक स्थान विशेष के दुष्कर्म के लिए सारे देश को सजा देने के लिए इस दोनो ने गाँधी की आलोचना की। मोतीलाल ने पूछा कि ''केप कामोरिन के पास कोई गांव अगर अहिंसक नही रह पाया तो हिमालय की तराई में किसी शहर को क्यों सजा दी जाए।''4

वी.डी सवारकर के अनुसार '' गाँधी द्वारा असहयोग आन्दोलन के साथ खिलाफत का प्रश्न जोड़ना कांग्रेस की बहुत बड़ी भूल थी। ए. आर. देसाई. के अनुसार, केवल भू–राजस्व को छोड़कर और किसी भी विषय पर आन्दोलन के कार्यक्रम में जन–साधारण की कोई विशिष्ट आर्थिक मांग नही थी। औद्योगिक बुर्जुआजी ने लड़ाई के दिनो में औद्योगिक प्रसार के कारण काफी आर्थिक ताकत हासिल कर ली थी। उनलोगों ने प्रायः असहयोग आन्दोलन का समर्थन किया। बारदोली के फैसले के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन का ह्रास हुआ। मुस्लिम लीग और कांग्रेस का परस्पर सहयोग समाप्त हो गया। और आन्दोलन के दौरान जो हिन्दू–मुस्लिम एकता उपरी तौर पर देखने में आई थी। वह खत्म होने लगी। 5

मृदुला मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संधर्ष में लिखा है कि गाँधी के आलोचको ने उनके साथ पूरी तरह न्याय नहीं किया। गाँधी शायद यह सोचते थे कि इस समय देशव्यापी आन्दोलन छेड़ने में हिंसा भड़क उठने का खतरा है, जैसा कि 1921 में मुबंई में और बाद में 1922 में चौरी–चौरा में हुआ। गाँधी को आशंका थी कि इस तरह कि कार्यवाइयो से अहिंसक असहयोग आन्दोलन की समूची रणनीति विफल हो जाएगी। साथ ही अहिंसक और निहत्थे, लोगो पर हमले से पूरा जनमत उनके खिलाफ हो जाएगा।

गाँधी का शायद यह अनुमान था कि चौरी–चौरा कांड ने बारदोली से व्यापक सविनय अवज्ञा आन्दोलन छोड़ने की संभावनओं को काफी हद तक कम कर दिया।6 मृदुला मुखर्जी ने आगे लिखा है कि गाँधी के आलोचक यह भूल जाते है कि कोई भी जनांदोलन लगातार लंबे अर्से तक नहीं चलता। उसमें पड़ाव आते है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद वह सुस्ताता है थकावट दूर करता है और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा जुटाता है। इसका मूल कारण यह है कि जनता की दमन सहने और बलिदान करने की शक्ति आसीमित नहीं होती है इस तरह कभी आन्दोलन वापस लेने की घोषणा या कभी समझौतावादी आख्तियार करना जनता पर आधारित राजनीतिक संघर्ष की सही रणनीति है। आन्दोलन को वापस लेना विश्वासघात नहीं हुआ करता यह तो रणनीति का हिस्सा है।7

स्वाधीनता की जो व्यापक लड़ाई है उसके अंतर्गत मजदूरो और किसानो की मांगे भी है जातियो के आत्मनिर्णय का अधिकार भी है। यह बात नहीं कहीं की गयी। नतीजा यह हुआ कि '' प्रगतिशील राजनीतिक पार्टियां– कांग्रेस और लीग में फूट और विघटन का जन्म हुआ। कांग्रेस में स्वराजपंथियों और अपरिवर्तनवादियों को दो दल बन गए।''8

निष्कर्षतः गाँधी जी के असहयोग आन्दोलन ने आत्मनिर्भरता एवं अपनी शक्ति संचित करने का पाठ पढ़ाया। सरकार भारतीयों के एच्छिक अथवा अनैच्छिक सहयोग पर निर्भर करती है।

असहयोग का कार्यक्रम और गाँधी की असाधारण प्रतिभा ने देशवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया।

संदर्भः–

1. सुभाषचन्द्र बोस, दि इडियन स्ट्रगल, मुंबई, एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1967, पृ0 90
2. जवाहरलाल नेहरू, आटोबायोग्राफी, लंदनः 1962, पृ0 86
3. रजनी पामदत्त, आज का भारत, दिल्लीः मैकमिलन इंडिया, 1985, पृ0 361
4. ए. आर. देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, नई दिल्लीः मैकमिलन इंडिया, 1988, पृ0 283
5. वही, पृ0 284
6. विपिन चन्द्र, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, दिल्लीः हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशायलय, 1991, पृ0 162
7. वही, पृ0 164
8. रामविलास शर्मा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, नई दिल्ली : राज कमल प्रकाशन, 1982, II , पृ0 461